उपेक्षित ग्रामीण डाक सेवकों ने तोड़ी चुप्पी

देहरादून (एसएनबी)। ग्रामीण डाक सेवकों ने डाक विभाग में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों की तरह वेतन-भत्ते व अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवक संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, वित्त मंत्री अरुण जेटली, संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद सहित पांचों सांसदों को ज्ञापन प्रेषित किया है।

- प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व संचार मंत्री को भेजा ज्ञापन
- विभागीय कर्मियों की तरह सुविधाएं देने की मांग

मनरेगा, डाक बीमा व वृद्धावस्था पेंशन जैसी योजनाएं शाखा डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा ही चलाई जाती हैं। ग्रामीणों को डाक सेवाएं देने के लिए ग्रामीण डाक सेवक प्रतिदिन दस घंटे से अधिक कार्य करते हैं। आश्चर्य की बात यह कि ग्रामीण डाक सेवकों के साथ भेदभाव गया है। ग्रामीण डाक सेवकों को न विभागीय कर्मचारियों की तरह बढ़ा वेतनमान व अन्य भत्ते मिलते हैं और न सुविधाएं। सातवें वेतन आयोग में भी ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन संरचना व सेवा शर्तों को शामिल करने से इनकार किया जा रहा है। संघ के मंडलीय सचिव आनंद सिंह रावत ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन संरचना व सेवा शर्तों को वर्ष 1946 में गठित पहले वेतन आयोग में शामिल किया गया था। उस समय इन कर्मचारियों को अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी के नाम से जाना जाता था। चौथे वेतन आयोग ने भी माना था कि अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी वेतन आयोग की परिधि में शामिल होने चाहिए। उन्होंने मांग की है कि ग्रामीण डाक सेवकों को विभागीय कर्मचारियों की तरह सुविधाएं दी जाएं।

शाखा प्रबंधक के बर्ताव के खिलाफ शिकायत

देहरादून (एसएनबी)। कोर सिक्योरिटी सर्विस के केयर टेकरों (कर्मचारियों) ने शाखा प्रबंधक के आपत्तिजनक व्यवहार की शिकायत पुलिस, लोकायुक्त, श्रम मंत्रालय व मानवाधिकार आयोग से की है। कर्मचारियों के अनुसार कुछ दिन पहले वे अपनी मांगों को लेकर शाखा प्रबंधक आनन्द से मिले तो उन्होंने कर्मचारियों से बेहद आपत्तिजनक तरीके से बात की और अपशब्द कहे। कंपनी के अधिकारियों से शिकायत करते हुए कर्मचारियों ने मांग की है कि शाखा प्रबंधक माफी मांगें। समान एरियर का भुगतान हो और ली गई रकम के बदले में वर्दी दी जाए। इसके अलावा कंपनी द्वारा दिए गए फर्जी आईकार्ड के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कंपनी अधिनियम के तहत साप्ताहिक अवकाश, राजपत्रित अवकाश व अन्य देय अवकाशों की सुविधा प्रदान की जाए। मांग करने वालों में महेन्द्र कुमार, मोहम्मद सत्तार, बिजेन्द्र सिंह, कमलेश सिंह, गौरीशंकर, खुर्शीद, धर्मेन्द्र, बसन्त, राजेश व जगदीश आदि शामिल रहे।

कलेक्ट्रेट में फिर हड़ताल शुरू

देहरादून (एसएनबी)। जिलाधिकारी के आश्वासन पर एक सप्ताह बाद खत्म हुई मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की हड़ताल एक दिन बाद फिर शुरू हो गई है। मिनिस्टीरियल कर्मियों का आरोप है कि जिलाधिकारी ने वापस लिए पुराने आदेश को हूबहू जारी करा दिया है। जिलाधिकारी से खफा मिनिस्टीरियल कर्मियों ने इसके बाद बेमियादी हड़ताल की घोषणा कर दी है। कर्मचारी फेडरेशन ने आठ अगस्त को प्रदेश की सभी कलेक्ट्रेट में कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। गुस्साए कर्मचारियों ने आज कार्यालय से निकलते समय जिलाधिकारी की गाड़ी का घिराव करते हुए उसे रोक लिया। इस पर जिलाधिकारी को पैदल ही एनआईसी के कार्यालय तक जाना पड़ा।

- डीएम पर पुराने आदेश को हूबहू लागू करने का आरोप लगाया
- जिलाधिकारी की गाड़ी रोकी, जाना पड़ा पैदल
- 8 अगस्त को पूरे प्रदेश के कलेक्ट्रेट में कार्यबहिष्कार

मिनिस्टीरियल कर्मचारियों की हड़ताल के बाद जिलाधिकारी ने स्टाफिंग पैटर्न के पुराने आदेश को वापस लेने की घोषणा करते हुए नया आदेश जारी करने का आश्वासन दिया था। इस पर मिनिस्टीरियल कर्मियों ने हड़ताल समाप्ति की घोषणा की। एक दिन बाद जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश से मिनिस्टीरियल कर्मचारियों मे फिर रोष पैदा हो गया। उत्तराखंड कलेक्ट्रेट मिनिस्टीरियल कर्मचारी संघ के अनुसार पुराने आदेश में से स्टाफिंग पैटर्न शब्द हटाकर आदेश को पूरी तरह उसी रूप में जारी कर दिया गया है। इससे गुस्साए मिनिस्टीरियल कर्मियों ने आज कार्यालय से निकलते समय जिलाधिकारी की गाड़ी को रोक लिया और जिलाधिकारी का घिराव किया।

काफी प्रयास के बाद भी कर्मचारियों ने गाड़ी को आगे जाने का रास्ता नहीं दिया। हर प्रयास असफल होने के बाद जिलाधिकारी को आखिरकार पैदल ही एनआईसी ऑफिस तक जाना पड़ा। फेडरेशन के श्री रावत ने कहा कि संगठन ने बेमियादी हड़ताल शुरू कर दी है। मांग पूरी होने तक हड़ताल वापस नहीं ली जाएगी। आंदोलन को सफल बनाने के लिए मिनिस्टीरियल फेडरेशन से संपर्क साधा जा रहा है। विरोध कर हड़ताल शुरू करने वालों में राजेन्द्र कुमार, देवेन्द्र सुन्दरियाल, आशीष वर्मा, सुखदेव, अजय सिंह, सुरेन्द्र, रविन्द्र, बालकराम जोशी, आशीष जोशी, सुशील बडोनी, मंजुला पुंडीर और रागिनी आदि शामिल रहे।

जिलाधिकारी की गाडी को रोकते मिनिस्टीरियल कर्मचारी।

मांगो को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय में नारेबाजी करते मिनिस्टीरियल कर्मचारी।

संक्षिप्त खबरें

मिनिस्टीरियल कर्मियों का कार्य बहिष्कार जारी

ऋषिकेश। पदोन्नति व स्थानांतरण संबंधी लंबित मामलों के निस्तारण की मांग को लेकर राजकीय महाविद्यालय मिनिस्टीरियल कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार बुधवार को भी जारी रहा। मिनिस्टीरियलकर्मी तीन घंटे तक कार्य से विरत रहे। मिनिस्टीरियल कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों पर शासन का रवैया उदासीन है। पदोन्नति व स्थानांतरण के संबंध में वार्ता के बाद भी शासन द्वारा समुचित कदम नहीं उठाया गया है। संगठन द्वारा कार्य बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। सतेसिंह रावत, विनोद कुमार, मीना रयाल, दिनेश नेगी, शकुंतला शर्मा व जोतसिंह भंडारी ने कहा कि जब तक लंबित मांगों का निस्तारण नहीं किया जाता, कार्यबहिष्कार जारी रहेगा।

महिला स्वास्थ्यकर्मियों की मुख्यमंत्री से गुहार

देहरादून (एसएनबी)। उत्तराखंड मातृ-शिशु एवं परिवार कल्याण महिला कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से मुलाकात कर उन्हें लंबित मांगों से अवगत कराया। एसोसिएशन की प्रांतीय अध्यक्ष गुड्डी मटूड़ा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिलने गए प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि आठ सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है।

- लंबित मांगों से कराया अवगत, मिला सकारात्मक आश्वासन

महिला स्वास्थ्य कर्मियों की मांग है कि उनका जिला कैडर समाप्त किया जाए। रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हो। महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों के 257 पद सृजित किए जाएं। 2800 रुपये का ग्रेड वेतन बढ़ाकर फार्मासिस्टों की तरह 4200 रुपये किया जाए। हड़ताल की अवधि के दौरान महिला स्वास्थ्य कर्मियों पर चलाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं। उपार्जित अवकाश को विशेष अवकाश में परिवर्तित किया जाए। मुख्यमंत्री ने महिला स्वास्थ्यकर्मियों को आश्वस्त किया कि न्यायोचित मांगों का समाधान किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में महामंत्री कांता राणा, मंजूबाला व विभा रानी आदि शामिल थीं।

कॉमर्शियल निर्माण पर एमडीडीए के तेवर हुए सख्त

देहरादून (एसएनबी)। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अवैध निर्माण को शह देने के आरोपों को धोने की कोशिश में जुटा है। पिछले एक महीने में प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ सख्ती से अभियान चला रखा है।

सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में अवैध निर्माण से संबंधित कई मामलों में सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए लंबित मामलों की फाइलों के निस्तारण में तेजी लाई गई है। लंबे समय तक एमडीडीए पर आरोप लगते रहे कि उसके अधिकारी अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं। अफसरों के द्वारा ऐसे मामलों में दिलचस्पी न लेने से इन आरोपों को बल मिला। बताया जा रहा है कि इसे लेकर शासन में बैठे अफसरों ने प्राधिकरण को आगाह किया। इसके बाद प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की रणनीति बनाकर कार्रवाई की। पिछले एक माह में प्राधिकरण ने तीन दर्जन से अधिक अवैध निर्माण सील किए हैं। वेडिंग प्वाइंटों पर की गई कार्रवाई इसी रणनीति का हिस्सा थी। वेडिंग प्वाइंटों को दुरुस्त करने के बाद प्राधिकरण के अफसरों ने अभियंताओं को हिदायत दी कि वे अपने इलाकों के अवैध निर्माण की शिकायतों का इंतजार करने के बजाय खुद नजर रखें। इस आदेश के बाद कई ऐसे प्रकरण भी सामने आए जो बिना किसी शिकायत के गलत मिले। प्राधिकरण की रणनीति है कि पहले व्यावसायिक उपयोग के लिए किए जा रहे अवैध निर्माण को रोका जाए। सूत्रों के अनुसार प्राधिकरण अवैध निर्माण के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। कंपाउंडिंग के लिए कैंप लगाने की तैयारी है।

अवैध निर्माण शहर के सुनियोजित विकास में बाधक है। इससे वहां रहने वाले लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे में प्राधिकरण की कोशिश है कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई करके शहर को व्यवस्थित रूप दिया जाए।

आर. मीनाक्षी सुंदरम, उपाध्यक्ष एमडीडीए

नालियों का निर्माण कार्य पूरा किया जाए

ऋषिकेश (एसएनबी)। चौदहबीघा क्षेत्र के नागरिकों ने पीडब्ल्यूडी नरेंद्रनगर से मुख्य सड़क पर नालियों के निर्माण कार्य को अविलंब पूरा करने की मांग की है।

बुधवार को मुनिकीरेती स्थिति लोनिवि कार्यालय में क्षेत्रवासियों ने सहायक अभियंता को संबोधित ज्ञापन सौंपा। बताया कि विभाग द्वारा दो माह पूर्व में मुख्य मार्ग का डामरीकरण किया गया था लेकिन बरसाती पानी की निकासी के लिए कुछ ही हिस्से में नालियों का निर्माण किया गया है। अभी भी मुख्य सड़क पर करीब 300 मीटर में नालियों का निर्माण शेष है जिससे बरसात के दौरान जगह-जगह जलभराव की स्थिति बन रही है।

उन्होंने चेताया कि जल्द ही उनकी मांग पर अमल नहीं किया गया, तो वह जनांदोलन को बाध्य होंगे। इस मौके पर गुरुप्रसाद बिजल्वाण, अनूप ध्यानी, हृदयराम सेमवाल, रवि शास्त्री, चंडीप्रसाद बडोनी, डीडी जोशी, प्रशांत भट्ट, खुशीराम सेमवाल, उपेंद्र जोशी आदि मौजूद थे।

छठे दिन भी धरने पर डटे रहे संग्रह अमीन

देहरादून (एसएनबी)। संवर्ग से जुड़ी विसंगतियों सहित अन्य मांगों को लेकर उत्तराखंड राजस्व संग्रह अमीन संघ का परेड ग्राउंड में चल रहा धरना छठे दिन जारी रहा। संग्रह अमीनों के आंदोलन के कारण राजस्व वसूली का कार्य ठप है। राजस्व विभाग के अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं।

बुधवार को धरनास्थल पर प्रदेशभर से आए संग्रह अमीन धरने में शामिल हुए। संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष उदयवीर सिंह रावत ने कहा कि शासन की अदूरदर्शी नीति के कारण राज्य के तमाम संवर्गों में विषमताएं पैदा हो गई हैं। सरकारी विभागों में चली आ रही विषमताएं सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन रही है। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व संग्रह अमीनों के धरने के कारण राजस्व वसूली का कार्य ठप है। अमीनों के पास सौंपे गए अन्य कार्य भी ठप हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष ने अमीनों की मांगों को समर्थन दिया है। परिषद ने कहा है कि सरकार ने जल्द अमीन संवर्ग की मांगें न मानी तो परिषद अमीन संघ के साथ हर कदम उठाने को तैयार है। छठे दिन धरने पर ऊधमसिंहनगर, देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग व उत्तरकाशी से आए संग्रह अमीनों ने शिरकत की। इस अवसर पर धीरेन्द्र कांडपाल, भूपेन्द्र बिष्ट, बलवंत सिंह बिष्ट, मुकेश पुंडीर, राकेश नेगी, सोहन लाल, धर्मवीर, सब्बल सिंह, द्वारिका प्रसाद बिजल्वाण, जसपाल राणा, रुकम दास, नरेन्द्र शर्मा, हर्षपति पोखरियाल, विरेन्द्र रावत, महिधर धस्माना, आशीष डोरा आदि उपस्थित थे।

- प्रदेशभर में राजस्व वसूली का काम ठप, अन्य कार्य भी हो रहे प्रभावित

धरनास्थल पर नारेबाजी करते संग्रह अमीन।

मुरली मनोहर यमुना पर धेनु चरावे..

देहरादून (एसएनबी)। लोकगीत व नृत्यों के माध्यम से कलाकारों ने भारत की अनेकता में एकता की झलक पेश की। मौका था ऑल इंडिया वूमेन कान्फ्रेंस की ओर से स्वतंत्रता दिवस व जन्माष्टमी पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों का। गणेश व सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का आरंभ किया गया।

बुधवार को इन्दर रोड स्थित भूपेन्द्र भृतहरि के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कथक गुरु बीना अग्रवाल की शिष्या प्रियांशी व वंशिका ने गणेश वंदना की खूबसूरत प्रस्तुति देकर दर्शकों को भावविभोर कर दिया। मुरली मनोहर यमुना तट पर धेनु चरावे.. की आकर्षक प्रस्तुति दी। सुरभि ने महाराष्ट्र का प्रसिद्ध लावणी नृत्य किया। सुकृति व शिखा रानी ने पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य पेश किया। राधिका व कनिका ने राजस्थानी लोकनृत्य की छटा बिखेरी। कार्यक्रम में अनिता गुप्ता, शोभा राजन, कविता बतरा को सुंदर परिधान के लिए पुरस्कृत किया गया।

धूमधाम से मनाया जाएगा 15 अगस्त

देहरादून (एसएनबी)। स्वतंत्रता दिवस को हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) झरना कमठान की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किये गये।

बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) झरना कमठान ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर समस्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्रातः छह से 8 बजे प्रभात फेरी निकाली जायेगी। साथ ही सभी कार्यालयों में प्रातः नौ बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। परेड ग्राउंड में प्रातः 10 बजे मुख्यमंत्री ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जनपद से लकेर पंचायत स्तर तक पौधरोपण किया जाएगा। इसके अलावा 14 अगस्त रात्रि 10 बजे से 16 अगस्त प्रातः 10 बजे तक जनपद में मद्यनिषेध रहेगा। विचार गोष्ठी, खेलकूद प्रतियोगिता, क्रास कन्ट्री रेस, साइकिल प्रतियोगिता आदि भी आयोजित की जाएगी।

- सभी कार्यालयों में सुबह नौ बजे ध्वजारोहण

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रताप शाह, डिप्टी कलेक्टर जिला मुख्यालय ललित नारायण मिश्रा, उप जिलाधिकारी मुख्यालय एनएस डांगी, नगर मजिस्ट्रैट गिरीश गुणवंत, उप जिलाधिकारी सदर मोहन सिंह बर्निया, मुख्य शिक्षा अधिकारी एसपी खाली, जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला आपदा प्रबन्धन अधिकारी दीपशिखा समेत अनेक अधिकार मौजूद थे।

पुलिस ने एक और अनशनकारी को उठाया

देहरादून (एसएनबी)। उत्तराखंड पॉलीटेक्निक संविदा शिक्षक सोसायटी का अनशन व धरना बुधवार को जारी रहा। बुधवार को तबीयत बिगड़ने पर पुलिस ने एक अनशनकारी को जबरन उठा लिया। इसके बावजूद संविदा शिक्षक आंदोलन पर डटे रहे।

धरना देते पॉलीटेक्निक संविदा शिक्षक।

बुधवार को हिंदी भवन के निकट अनशन पर बैठे संदीप उनियाल की हालत बिगड़ गई। इसके बाद दोपहर करीब 12 बजे पुलिस ने संदीप को जबरन उठाकर चिकित्सालय में दाखिल करा दिया। चार संविदा शिक्षक अनशन पर डटे हैं। सोसायटी अध्यक्ष सर्वेश चौधरी ने कहा कि सरकार संविदा शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने पांच सूत्री मांगों के पूरा होने के बाद ही आंदोलन समाप्त होगा।

- तबीयत बिगड़ने पर उठाया अनशनकारी को, इसके बाद भी आंदोलन पर डटे हैं संविदा शिक्षक

इस मौके पर महेश कुमार, महेश भट्ट, अशोक कुमार, मुकेश सिंह, नरेण पाठक, सिमरन बडवाल, कविता भंडारी, मुनीर, नमिता तिवारी, पंकज डागर व नंदकिशोर सती आदि मौजूद थे।

अवैध कब्जों को हटाने की मांग की

देहरादून (एसएनबी)। शैल शिखर सामाजिक संस्था ने वार्ड संख्या 54 में हो रहे अवैध कब्जों पर चिंता जताते हुए मुख्य नगर अधिकारी से अवैध कब्जों को हटाने की मांग की है। कांग्रेस नेता सूर्यकान्त धस्माना के नेतृत्व में मुख्य नगर अधिकारी हरक सिंह रावत को ज्ञापन सौपते हुए संस्था के प्रबंधक अरुण शर्मा ने कहा कि वार्ड 54 में श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल से लगती भूमि पर खानाबदोश लोगों ने अवैध कब्जा किया है। खानाबदोश लोग इस पर पक्के निर्माण करने लगे हैं। नगर निगम की भूमि पर हो रहे अवैध कब्जों से शहर की सूरत बिगड़ रही है। उन्होंने एमएनए से शिकायत करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों द्वारा ही सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे कराए जा रहे हैं। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द अवैध कब्जे हटाने की मांग की है। मुख्य नगर अधिकारी से मिलने वालों में दिव्यांत जोशी, सौरभ शर्मा, मदनमोहन, रमेश, मनीष, अशोक, मोहिता व अन्य शामिल रहे।

रमसा कर्मियों व शिक्षाचार्यों का धरना जारी

देहरादून (एसएनबी)। अनुबंध बढ़ाने की मांग को लेकर आउटसोर्सिंग कार्मिक संघ (रमसा) का धरना सातवें दिन भी जारी रहा। वहीं शिक्षा मित्र पद पर समायोजन की मांग को लेकर शिक्षाचार्यों व अनुदेशकों का भी धरना जारी रहा।

बुधवार को शिक्षा निदेशालय के सम्मुख संघ के अध्यक्ष अध्यक्ष सुभाष लखेड़ा, उपाध्यक्ष वीपी सती, महासचिव आनन्द बड़ोनी, मीडिया प्रभारी योगेन्द्र बड़ोनी समेत बड़ी संख्या में लोगों ने धरना दिया। संघ के अध्यक्ष सुभाष लखेड़ा ने कहा कि शासन द्वारा आश्वासन देने के बाद भी अनुबंध का नवीनीकरण नहीं हुआ है जिससे कार्मिकों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई न होने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।

- मांगों पर कार्रवाई न होने पर दी आंदोलन तेज करने की चेतावनी

दूसरी ओर, हिन्दी भवन के निकट शिक्षाचार्य व अनुदेशक संगठन का धरना 795वें दिन भी जारी रहा। प्रान्तीय अध्यक्ष देवेन्द्र सिंह बिष्ट ने कहा कि समायोजन को मंजूरी मिलने के पांच माह में भी शासनादेश आज तक जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही समायोजन का शासनादेश जारी न होने पर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। धरना देने वालों में देवेन्द्र सिंह बिष्ट, रतिराम, खेम सिंह, मो. शमशाद, शशी मिश्रा, लक्ष्मी, सीमा, सरिता आदि शामिल थे।

शिक्षा निदेशालय में धरना देते आउटसोर्सिंग कर्मचारी।

पीआरडी जवान आंदोलन की राह पर

देहरादून (एसएनबी)। पीआरडी जवानों ने शासन-प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आश्वासन देने पर भी पांच सूत्री मांगों का समाधान नहीं हुआ है। ऐसे में उन्होंने दोबारा आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।

प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद कुमार मंद्रवाल ने कहा कि यदि 15 दिनों में उनकी लंबित मांगों का समाधान नहीं होता है तो प्रदेशभर के पीआरडी जवान आगामी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। उन्होंने निदेशालय प्रांगण में भूख हड़ताल करने की चेतावनी भी दी है। बुधवार को हिंदी भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में श्री मंद्रवाल ने कहा कि पीआरडी जवान सचिवालय, विधानसभा की सुरक्षा, चुनाव के दौरान ड्यूटी करते हैं। सभी जगह पीआरडी जवान मुस्तैदी से तैनात रहते हैं। चालक, कम्प्यूटर आपरेटर, चौकीदार, माली व कुक के पदों पर भी पीआरडी जवान कार्य कर रहे हैं। वह भी बेहद कम वेतन व सुविधाओं में। उन्होंने कहा कि पीआरडी एक्ट में संशोधन कर पीआरडी जवानों का नियमितिकरण करना, अलग ढांचा तैयार कर युवा कल्याण विभाग से पृथक करना, ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो जाने पर दस लाख रुपये का बीमा लाभ देना आदि मांगों को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन किया जा चुका है। पिछले वर्ष पीआरडी जवानों ने परेड ग्राउंड में 123 दिनों तक धरना दिया था। इसके बाद शासन ने वार्ता के लिए बुलाकर पीआरडी जवानों की मांगों का समाधान 15 दिनों में करने का आश्वासन दिया था। सालभर बीत जाने के बावजूद मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई है। पीआरडी जवानों के पास दोबारा आंदोलन शुरू करने के सिवाय विकल्प नहीं है। पत्रकार वार्ता में सुनील चौहान, सत्यपाल सिंह आदि पीआरडी जवान मौजूद रहे।

- 15 दिनों में मांगों का समाधान न हुआ तो 18 अगस्त से शुरू करेंगे हड़ताल, शासन-प्रशासन पर लगाया वादाखिलाफी का आरोप

पत्रकार वार्ता करते हुए प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पीके मंद्रवाल व अन्य

बसपा ने भेजा पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन

ऋषिकेश (एसएनबी)। नगर में बढ़ रही अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लागने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जोनल को-आर्डिनेटर रवि कुमार जैन ने पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भेजा।

बुधवार को बसपा जोनल को आर्डिनेटर रवि कुमार जैन ने पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू को ज्ञापन भेजा। जिसमें उन्होंने अवगत कराया कि शहर में पुलिस की लापरवाही के चलते पिछले कुछ दिनों से चोरी, हत्या एवं चेन स्नेचिंग के कई मामले सामने आये हैं। इनके खुलासे को लेकर पुलिस अंधेरे में हाथ-पांव मार रही है उन्होंने कहा कि नगर में पिछले कई वर्षों से शराब का अवैध धंधा जोरों पर है लेकिन पुलिस की विफलता के कारण शराब तस्करों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। ज्ञापन भेजने वालों में अरविन्द शाह, दीनदयाल अग्रवाल, प्रदीप कुमार, परमेश्वर राजभर, लल्लन राजभर, पंकज जाटव, अशोक जाटव, प्रवेश कुमार आदि शामिल थे।

संविदा कर्मियों ने किया बुद्धि-शुद्धि यज्ञ

देहरादून (एसएनबी)। नौकरी से बाहर किये गये ओएनजीसी हास्पिटल के पैरामेडिकल स्टाफ के संविदा कर्मचारियों का धरना बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। संविदा कर्मचारियों ने ओएनजीसी अस्पताल के गेट पर प्रबंधन की सद्बुद्धि के लिए बुद्धि-शुद्धि यज्ञ किया। मांगों का समाधान नहीं होने पर उन्होंने उग्र आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है।

भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले धरनारत पैरामेडिकल स्टाफ के संविदा कर्मचारियों का कहना है कि ओएनजीसी ने बिना लिखित सूचना के उन्हें नौकरी से बाहर किया है। पैरामेडिकल स्टाफ के कर्मचारी पिछले डेढ़ दशक से ओएनजीसी अस्पताल में ड्यूटी कर रहे थे। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि प्रबंधन ने न्यायालय व श्रमायुक्त के आदेश को दरकिनार किया है। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने भी संविदा कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि संविदा कर्मचारी पिछले छह दिन से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन प्रबंधन का कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। ओएनजीसी प्रबंधन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटा रहा है। रतनाल, रमेश, विमल चंद्रा, नितिन, मेहरबान नेगी, पवन, शैली, देवप्रभा, स्मारिका आदि संविदा कर्मचारी भी धरने पर बैठे।

- ओएनजीसी अस्पताल के गेट पर कर्मचारियों का धरना छठे दिन भी जारी
- मांगों का समाधान नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान

बुद्धि-शुद्धि यज्ञ करते ओएनजीसी हॉस्पिटल के पैरामेडिकल संविदा कर्मचारी।